



जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दस्तक

छह राज्यों ने किया कानून लागू करने से इनकार

जनसत्ता ब्यूरो/एजेंसी नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, छात्र संगठन आल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसु) सहित कई याचियों ने नागरिकता संशोधन कानून (कैब) की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को याचिकाएं दायर कीं। इन अर्जियों में कहा गया है कि नागरिकता कानून में संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे और समता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का हनन करता है।



गुवाहाटी में शुक्रवार को पेट्रोल पंप पर उमड़ी भीड़।

जापानी प्रधानमंत्री का भारत दौरा रह

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 दिसंबर।



जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत दौरा रह कर दिया गया है। नागरिकता कानून को लेकर असम में भारी विरोध प्रदर्शन के कारण 15-17 दिसंबर को

असम व पूर्वोत्तर की आग पहुंची बंगाल

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

नागरिकता कानून के विरोध में असम समेत पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में कर्फ्यू एवं निषेधाज्ञा के बावजूद विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। विरोध प्रदर्शनों में तीन लोग मारे जा चुके हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी समेत

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निकाय ने भारत के नए नागरिकता कानून को लेकर चिंता जताई।

अमेरिका ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का अनुरोध किया

खबरें पेज 13 पर



विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

नागरिकता कानून को लेकर पूर्वोत्तर में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच विभिन्न राज्यों ने इसे लागू करने से मना करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने इस कानून को लागू करने से मना कर दिया। पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब ने पहले ही मना कर दिया था। महाराष्ट्र में कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और वहां की उद्वेग सरकार में मंत्री बाला साहेब थोरट ने इस बाबत एलान किया। दूसरी

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने भी पकड़ी बंगाल, पंजाब और केरल की राह



राज्यों को इनकार का हक नहीं : केंद्र - खबरें पेज 8 पर

ओर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस आशय की बातें बाकी पेज 8 पर

संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान पर हमला

हर बड़े आतंकी हमले के तार पाक से जुड़ते हैं

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए भारत ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के हर बड़े कुकृत्य के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए आतंकवाद के इस पनाहगाह में प्रशिक्षण दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर का मसला उठाए जाने और नागरिकता कानून का हवाला दिए जाने के बाद भारत ने

जब लोमड़ी, मुर्गी की रखवाली कर रही होती है तो हमें विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत होती है।

-पालोमी त्रिपाठी, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव

पलटवार किया है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पालोमी त्रिपाठी ने महासभा में 'शांति की संस्कृति' बाकी पेज 8 पर

राहुल के बयान पर लोकसभा में हंगामा, माफी मांगने की मांग

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बलात्कार मामलों को लेकर कथित टिप्पणी पर शुक्रवार को लोकसभा में भाजपा सदस्यों ने भारी हंगामा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के बयान से पूरा देश आहत हुआ है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और ऐसे बयान देने वाले सदस्य को सदन में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।

राहुल गांधी के बयान से पूरा देश आहत हुआ है। - राजनाथ सिंह

यह बयान भारत की महिलाओं और देश का अपमान है। -स्मृति ईरानी

राहुल का माफी मांगने से इनकार

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (जनसत्ता ब्यूरो/भाषा)।

बलात्कार पर कथित टिप्पणी को लेकर भाजपा के हमलों से घिरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि वे इस मुद्दे पर कभी माफी नहीं मांगने वाले।

राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, 'जहां तक माफी की बात है तो मैं कभी इनसे माफी मांगने वाला नहीं हूँ।' कांग्रेस नेता ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा- मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैंने क्या बोला। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 'मेक इन इंडिया' होगा। हमने सोचा कि अखबारों में 'मेक बाकी पेज 8 पर

'मजबूत मालदीव के लिए भारत प्रतिबद्ध'

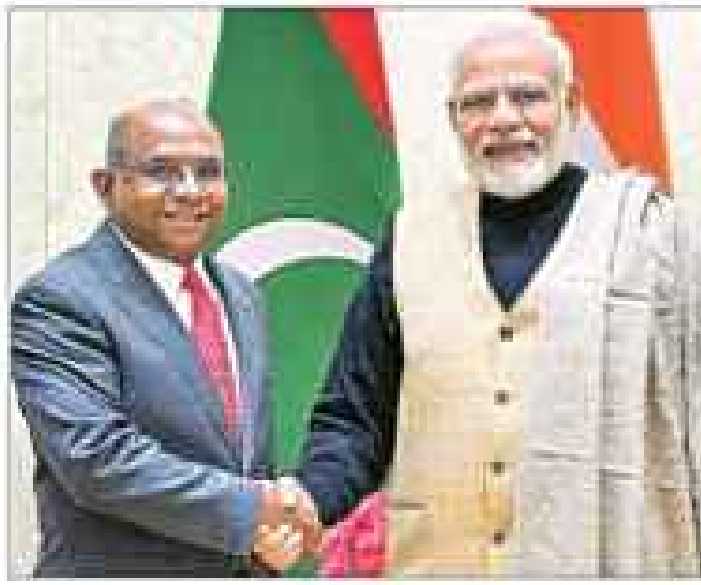
जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मालदीव के बीच बेहतर संपर्क एवं द्विपक्षीय संबंधों के सकारात्मक नतीजों पर संतोष जताया है और कहा कि भारत शांतिपूर्ण, समृद्ध, लोकतांत्रिक एवं मजबूत

मालदीव के निर्माण के लिए वहां की सरकार के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात के दौरान ये बातें कहीं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को मालदीव के अपने समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात

भारत शांतिपूर्ण, समृद्ध, लोकतांत्रिक, मजबूत मालदीव के निर्माण के लिए वहां की सरकार के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। - नरेंद्र मोदी

मालदीव के विदेश मंत्री शाहिद ने भारत- मालदीव संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी दृष्टि और मजबूत नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।



प्रधानमंत्री ने मालदीव के विदेश मंत्री से मुलाकात की।

की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गति देने के लिए व्यापक चर्चा की। दोनों

मंत्रियों ने बिना किसी सहयोगी के वार्ता की। प्रधानमंत्री कार्यालय बाकी पेज 8 पर

मतों की संख्या में विसंगतियों पर चुनाव आयोग को नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनावों में 347 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान और गणना में मतों की संख्या में कथित विसंगतियों की जांच के लिए दो गैर सरकारी संगठनों की जनहित याचिका पर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले पीठ ने इसके साथ ही इन याचिकाओं को पहले

बाकी पेज 8 पर



कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग पहुंची भाजपा की महिला सांसद -खबरें पेज 8 पर

आरंभ होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए और ऐसे बयान देने वाले को इस सदन का सदस्य रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी के बयान से यह सदन और पूरा देश आहत हुआ है। 15 मिनट बाद सदन शुरू होने

दोषी की याचिका के खिलाफ अदालत पहुंची निर्भया की मां

जनसत्ता ब्यूरो/संवाददाता नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषियों में से एक अक्षय की पुनर्विचार याचिका का विरोध करते हुए पीड़िता की मां ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया। दिसंबर, 2012 के इस सनसनीखेज अपराध के चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है। इनमें से तीन मुजरिमों की पुनर्विचार याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। अक्षय के अलावा तीन अन्य दोषियों के पास अभी भी शीर्ष अदालत में अपनी



सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को सुनवाई

दोषिसिद्धि और मृत्युदंड के फैसले में सुधारात्मक याचिका दायर करने का विकल्प है। शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए चौथे मुजरिम अक्षय कुमार की याचिका पर 17 दिसंबर को तीन न्यायाधीशों का पीठ सुनवाई करेगा। पीड़िता की मां के वकील ने प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि वे दोषी की पुनर्विचार याचिका का विरोध कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि पीड़िता की मां के वकील की बात भी 17 दिसंबर

सबरीमला पर किसी नए आदेश से इनकार

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सबरीमला मंदिर में पुलिस की सुरक्षा में महिलाओं का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए केरल सरकार को कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह बहुत ही भावनात्मक विषय है और वह नहीं चाहता कि स्थिति विस्फोटक हो। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति वीआर गवई और न्यायमूर्ति सुर्य कांत

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में एक फैसला है। मामले को वृहद पीठ को सौंप दिया गया है। मैंने अभी तक वृहद पीठ गठित नहीं की है। सहूलियत के संतुलन के लिए जरूरत है कि हम आज कोई आदेश नहीं दें। - प्रधान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट

सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाले 28 सितंबर, 2018 के फैसले पर किसी प्रकार बाकी पेज 8 पर

दरअसल



दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में कड़ाके की ठंड मौसम की करवट जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में पहले से ही बर्फबारी

पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठिठुरन

जनसत्ता टीम नई दिल्ली/देहरादून 13 दिसंबर।

पहाड़ों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ओले के साथ तेज बारिश होने से मौसम ने एकदम से करवट बदला है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सहित तमाम इलाकों में इसके साथ ही ठिठुरन बढ़ गई है। बारिश से प्रदूषण में भी कमी दर्ज हुई। उत्तराखंड, नैनीताल, मसूरी और उसके आसपास उंचाई वाले स्थानों पर शुक्रवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई। जबकि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में पहले से चल रही बर्फबारी शुक्रवार को भी जारी रही। कुछ दिनों



में घना कोहरा छाने के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी

पश्चिमी विक्षोभ का असर

दिल्ली-एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हुई और ओले पड़े। तमाम पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी भी पश्चिमी विक्षोभ का ही नतीजा रही। इसके आगे भी जारी रहने की संभावना है।

हुई बर्फबारी भी पश्चिमी विक्षोभ का ही नतीजा रही। इसके आगे भी जारी रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों से आ रही हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली का अधिकतम तापमान औसत से दो डिग्री कमी के साथ 21.8 दर्ज किया गया। पालम में 40.2 मिलीमीटर बारिश के साथ तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री दर्ज किया गया। लगातार बारिश के कारण उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के कारण पर्वत बर्फ से लकड़क हो गए हैं। नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा बागेश्वर, टिहरी चंपावत रुद्रप्रयाग समेत राज्य बाकी पेज 8 पर

रविवारी
15 दिसंबर, 2019

मानसिकता में खोटे

बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को रोकने की मंशा से कई कड़े प्रावधान किए गए, पर उनमें निरंतर बढ़ती ही दर्ज हो रही है। इसके पीछे बड़ी वजह दूषित मानसिकता है। बता रही हैं नाज खान।

- कविता/ शंकरानंद • कहानी/ विमल सेन सिंह
- ललित प्रसंग/ सुरेश सेठ • योग दर्शन/ डॉ. वरुण वीर • शक्तिस्थल/ श्रीनिवास रामानुजन • दाना-पानी/ मानस मनोहर • सेहत/ रविवारी डेस्क

सर्दी और बेशुमार स्टाइल • दीपति अग्रिवा • कविता/ शिव मोहन यादव • कहानी/ सुधा गुप्ता 'अमृता'

दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र
 (संस्कृति मन्त्रालय, भारत सरकार)
 दक्षिणी, मेडिकल कॉलेज रोड, थंजावुर-613 004, तमिलनाडु

सीधी भर्ती द्वारा निम्नलिखित पदों हेतु आवेदन आमन्त्रित करता है

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	श्रेणी	वेतनमान	15.12.2019 को आयु सीमा
01.	प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव	3	अना.	रु. 35400(पीएल-6)	न्यूनतम 18 वर्ष-अधिकतम 30 वर्ष
02.	असिस्टेंट प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव	2	अना.	रु. 25500(पीएल-4)	न्यूनतम 18 वर्ष-अधिकतम 25 वर्ष
03.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1	अना.	रु. 35400(पीएल-6)	न्यूनतम 18 वर्ष-अधिकतम 30 वर्ष
04.	कनिष्ठ सहायक	2	अना.	रु. 25500(पीएल-4)	न्यूनतम 18 वर्ष-अधिकतम 25 वर्ष

विवरण तथा आवेदन प्रपत्र वेबसाइट szccindia.org से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में निदेशक, दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, थंजावुर के पक्ष में थंजावुर में देय रु. 100/- के पोस्टल ऑर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट (अ.जा./अ.ज.जा. तथा महिला अभ्यर्थियों हेतु उपर्युक्त शुल्क से छूट है) सहित आवेदन निदेशक के पास उपर्युक्त पते पर भेजने हैं। आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 17 जनवरी, 2020 है।

ह./- निदेशक
 दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
 थंजावुर
 davp 09132/11/0006/1920

'विद्यार्थियों को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाएगी सरकार'

जनसत्ता संवाददाता
 नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार विद्यार्थियों को शिष्ट आचरण का पाठ पढ़ाएगी। इसकी मदद से बच्चों को समाज में हो रहे महिला अपराधों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों व कॉलेजों में बच्चों को शपथ दिलाई जाएगी कि वे महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं करेंगे।

केजरीवाल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरा देश चिंतित है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार घटनाएं बढ़ रही हैं इस क्षेत्र में सरकार अपने काम करेगी लेकिन हम एक विशेष अभियान शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल व कॉलेजों में लड़कों को शपथ दिलावाएंगे कि कभी भी किसी महिला के साथ कोई दुराचार या व्यवहार नहीं करेंगे। बहन भी अपने भाई को यह शपथ दिलाएंगी।

उन्होंने कहा कि केवल शपथ दिलाने से काम नहीं होगा। अगर ऐसी घटना कहीं पर होती है तो ऐसे व्यक्ति का परिवार को बहिष्कार करने की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री

मनीष सिंसोदिया ने कहा कि समाज में इन घटनाओं पर चर्चा करने की जरूरत है, इससे इसका रास्ता निकल सकेगा। यह शपथ कक्षा 6 से कॉलेज स्तर तक के बच्चों के लिए होगी।

केजरीवाल की मालीवाल से अनशन तोड़ने की अपील

महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का धरना शुकवार को भी जारी रहा। अनशन की वजह से स्वाती मालीवाल की बिगड़ रही स्वास्थ्य स्थिति पर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने मालीवाल से अपील की कि अब उन्हें अनशन छोड़ देना चाहिए। उनकी सेहत व जिंदगी बेशकीमती है। उन्होंने कहा कि केवल शपथ दिलाने से काम नहीं होगा। अगर ऐसी घटना कहीं पर होती है तो ऐसे व्यक्ति का परिवार को बहिष्कार करने की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री

महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए दिल्ली सरकार की कोशिश



स्वर्णगंगा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
 U45400DL2011PTC216126
फार्म नं. आइएनसी-26
 [कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
 एक राज्य से अन्य राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन **केंद्र सरकार के समक्ष**
 क्षेत्रीय निदेशक-उत्तरी क्षेत्र के माध्यम से कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खंड (ए) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप धारा (4) के विषय में।
 तथा स्वर्णगंगा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-141 डीडीए रोड ओखला फेज-1, नई दिल्ली 110020

शुद्धिपत्र-1
 दिनांक 14.12.2019 को प्रकाशित "एनएससीआई एक्सप्रेस", कोलकाता में एचएन एवं टैक्सि लिंक (नारायणपुर वाइड) को जोड़ने के लिए ती श्रेणी एयरक्राफ्ट के लिए 3 ईईएन का निर्माण।
 उधारी: मोटोरोइलक रलाइडिंग बंट का बीएसआईटीसी कार्य के लिए निवेदन आदेशों में 2019_AAI 26217_1 का संदर्भ में।
 ई-निविदा बरतवेंज नाम करने की अंतिम तिथि एच समाज 16.12.2019 को 1800 बजे तक बढ़ा दी गई है। निरूपण जानकारी के लिए बीबीपी ई-इंफोर्मेशन पोर्टल वेबसाइट <http://www.bids.gov.in> पर जा सकते हैं।
 डाउनलोड या www.mca.gov.in पर जा सकते हैं।

CSL Finance Limited
 Regd. Office: 470-472, 13/12, 47 Floor, M.E.A. Argo Sama Bldg, Karol Bagh, New Delhi-110005
 (CIN: U74103DL1997PLC001400) Tel: 92264-09696, Email: info@cslfinance.in, Web: www.cslfinance.in
 Extract of Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2019

Particulars	QUARTER ENDED 30.09.2019	HAIF YEAR ENDED 30.09.2019	QUARTER ENDED 30.09.2018
	(IN AUDIT)	(IN AUDIT)	(IN AUDIT)
1. Total income from operations	5212.53	10515.54	5396
2. Net Profit (Loss) for the period	525.29	1044.82	831.55
3. Net Profit (Loss) for the period before tax (after deducting cost of extraordinary items)	525.29	1044.82	831.55
4. Net Profit (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items for extraordinary items)	724.89	1378.15	597.33
5. Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit (Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income (after tax))	724.89	1378.15	597.33
6. Equity Share Capital	606.83	639.33	686.66
7. Reserves (including Provisional Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	2047.45	2947.45	1714.84
8. Earnings Per Share of Rs. 10/- (after deducting cost of extraordinary items)			
1. Basic	11.76	22.34	9.18
2. Diluted	11.66	22.17	9.14

Notes:
 1. This is a condensed extract of the detailed Un-audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Quarterly Financial Results of the quarter and half year ended 30.09.2019 are available on the Stock Exchange website: www.sebi.gov.in or on the company's website at www.cslfinance.in.
 2. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 13.12.2019.
 3. The above Financial Results have been prepared in accordance with principles laid down in Indian Accounting Standards.

Place: New Delhi
 Date: 11.12.2019

सूचना
 सामान्य जनता को एवढा सूचना दी जाती है कि कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय "केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली" से "राजस्थान राज्य" में बदलने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए दिनांक 19 नवंबर, 2019 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार मेमोरेडम ऑफ असोसिएशन के परिवर्तन को पुष्टि मांगने के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अंतर्गत केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के माध्यम से) को आवेदन करना प्रस्तावित है।
 कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 बिल्डिंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को विरोध के कारण तथा शिष्ट की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या कार्यालय को भेजें या निदेशक शिकायत प्रपत्र भरने द्वारा एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर डिजिटल करने के साथ उसकी प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय बी-141 डीडीए रोड ओखला फेज-1, नई दिल्ली 110020 पर भेजनी है।
 दिने एवं कृते आवेदक कृते स्वर्णगंगा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
 हस्ता./-
 मनीष कुमार गिखारियाल लट
 दिनांक: 14.12.2019
 स्थान: नई दिल्ली (DIN 00102935)

जीवन लाभ
 सीमित प्रीमियम एंडोमेंट प्लान
 Plan No.: 835 : LHM No.: 512M04V01

आवर्षिक लाभों के साथ जीवन बीमा सुरक्षा

वित्तीय आयु	प्रीमियम शुभानाम आयु
16	10
21	15
25	16

- न्यूनतम मूल बीमा राशि : ₹200,000/-
- अधिकतम मूल बीमा राशि : कोई सीमा नहीं
- प्रवेश की आवश्यकता : 8 वर्ष
- प्रवेश की अधिकतम आयु : वित्तीय आयु 25/21/16 वर्ष के लिए 50/54/59 वर्ष
- वैयक्तिक शिफारिश :
 (i) एमआईसी का न्यूनतम मूल्य एवं विकल्पों का विवरण संचालक
 (ii) एमआईसी का नया रम एवम् एवोल्यूशन संचालक

फायदे चलते रहें.

आपने एवमेंट / सहायता से सम्पर्क करें या हमारी वेबसाइट www.lifecorner.com पर विजिट करें या SMS करें आपके शहर का नाम, 56767474 पर

Follow Us: [Facebook](#) [YouTube](#) [LIC India Forever](#) IRDAI Regn No.: 512

आपका श्रेष्ठ कोशिस बना करमी / पोषणही नाने अतिरिक्त से शुरुआत
 अर्थात् (अवसरों का महासागर) का इच्छा अतिरिक्त, बीमा विज्ञान या विज्ञान केन्द्र के माध्यम से बीमा प्रतिक्रिया से स्वयं नहीं स्वयं।
 • अर्थात् (अवसरों का महासागर) का इच्छा अतिरिक्त, बीमा विज्ञान या विज्ञान केन्द्र के माध्यम से बीमा प्रतिक्रिया से स्वयं नहीं स्वयं।

बीमा सुरक्षा से पूर्व अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध करते हैं, नियम और शर्तों के लिए पालन की विधि के लिए कृपया बीमा प्रतिक्रिया से स्वयं नहीं स्वयं।

LIC
 भारतीय जीवन बीमा निगम
 LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
 LIC/01/13/0900111
 वित्तीयों के साथ भी, वित्तीयों के साथ भी.

भारतीय नौसेना
अवसरों का महासागर
 10+2 (बी.टेक) कैडेट एन्ट्री स्कीम (स्थायी कमीशन)
 कोर्स प्रारम्भ-जुलाई 2020

भारतीय नौसेना उन अविवाहित पात्र पुरुष अभ्यर्थियों से जिन्होंने सीनियर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2 पैटर्न) पर या किसी बोर्ड से इसके समकक्ष परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित (पीसीएम) में न्यूनतम 70% तथा अंग्रेजी में न्यूनतम 50% (या तो कक्षा X में या कक्षा II में) सहित उत्तीर्ण की, 10+2 (बी.टेक) के तहत चार वर्षीय डिग्री कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन आमन्त्रित करती है।

आयु सीमा
 02 जनवरी, 2001 तथा 01 जुलाई, 2003 (दोनों तिथियाँ शामिल) के बीच जन्म हुआ हो।

नोट :

- अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण तथा अपने आवेदन 29 नवम्बर से 19 दिसम्बर, 2019 के बीच भर्ती की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जमा करने होंगे। आवेदन जमा करने की खिड़की पर समय बचाने के लिए अभ्यर्थी अपने विवरण अग्रिम रूप से भरकर दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं।
- ऑनलाइन (ई-आवेदन) : ई-आवेदन भरते समय व्यक्तिगत विवरण उचित रूप से भरने में सक्षम होने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज पहले से तैयार रखने का परामर्श दिया जाता है।
- विवरण मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट/12वीं के सर्टिफिकेट में दिये गये के अनुसार भरे जाने हैं।
- ई-मेल पते, मोबाइल नम्बर जैसे स्थान अनिवार्य रूप से भरे जाने हैं।
- आवेदन भरते समय अटैच करने के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज (विशेष रूप से मूल रूप में), जन्म प्रमाण पत्र (10वीं/12वीं के प्रमाणपत्रों के अनुसार), 10वीं की अंकतालिका, 12वीं की अंकतालिका, जेईई (मेन)-2019 का स्कोर कार्ड (अखिल भारतीय रैंक प्रदर्शित करते हुए तथा हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ मूल रूप में स्कैन करके जेपीजी/टिफ प्रारूप में)।
- यदि किसी कारण से स्कैन किया गया दस्तावेज अस्पष्ट/अपठनीय है तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति का प्रिंट लेकर एसएसबी साक्षात्कार के समय मूल प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों के साथ लाएँ।

महत्त्वपूर्ण :

- विस्तृत सूचना तथा चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित पूर्ण विज्ञापन 23 नवम्बर, 2019 के रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जायेगा और साथ ही यह www.joinindiannavy.gov.in पर भी उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी 29 नवम्बर से 19 दिसम्बर, 2019 तक आवेदन कर सकते हैं। अन्तिम समय की भीड़ से बचने के लिए आवेदन शीघ्र करने का परामर्श दिया जाता है।
- अपने ऑनलाइन आवेदन अन्तिम रूप से जमा करने से पूर्व वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
- आपका आवेदन बाद की जाँच का विषय है। यदि किसी भी समय आवेदन अपात्र/अवैध पाया जाता है तो वह निरस्त किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन बन्द होने के पश्चात अपलोड किये गये दस्तावेजों में संशोधन के लिए किसी निवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई धोषणा गलत पायी जाती है तो आपका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा।
- इस विज्ञापन में दिये गये नियम एवं शर्तें परिवर्तित हो सकती हैं और इसलिए इसे केवल दिशा-निर्देश के रूप में लिया जाना चाहिए।

क्यूआर कोड के माध्यम से आवेदन करें
 चरण 1 : क्यूआर कोड स्कैनर एप डाउनलोड करें
 चरण 2 : क्यूआर कोड एप खोलें और इसे स्कैन करें
 चरण 3 : यूजरएल खोलें और निर्देशों का अनुपालन करें

	मौसम				
<i>तापमान</i> नोएडा गाजियाबाद गुरुग्राम फरीदाबाद					
अधिकतम	18.7 डि.से.	18.7 डि.से.	18.5 डि.से.	19.0 डि.से.	
न्यूनतम	12.8 डि.से.	12.8 डि.से.	12.7 डि.से.	12.8 डि.से.	

जनसत्ता, नई दिल्ली, 14 दिसंबर, 2019 4

नागरिकता कानून के खिलाफ नागरिक संगठन सड़क पर उतरे

जामिया के युवाओं की पुलिस से झड़प

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली में शुक्रवार को कई विरोध प्रदर्शन किए गए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों का प्रदर्शन तो हिंसक हो गया। छात्रों का मार्च रोकने के कारण प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी विश्वविद्यालय से निकलकर संसद भवन की ओर जाना चाह रहे थे। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने लाठियां चलाई। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। छात्रों ने भी पथराव किया। पुलिस ने सड़क को घेर दिया तो प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ गए।

संसद मार्ग, जंतर मंतर पर जमघट रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के परामर्श के बाद ऐतिहायत के तौर पर दिल्ली मेट्रो रेलवे कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने पटेल चौक और जनपथ मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वारों को घंटो बंद कर दिया गया। देर शाम उन्हें फिर खोल दिया गया। इसमें कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं।

मजदूर किसान शक्ति संगठन के बैनर तले अरुणा राय, शंकर सिंह, और निखिल डे ने उम्मीद जताई कि सुप्रिम कोर्ट इस तरह से भारतीय संविधान के मूल ढांचे को कमजोर नहीं होने देगा। उन्होंने कहा-यह कानून भेदभाव और पक्षपातपूर्ण है।

नागरिक संगठनों की ओर से रवि नायर, अनिल चमडिया, मौलाना अंसगर अली, नवेद हामिद जफर महमूद, सलीम इंजीनियर आदि ने



जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई।

प्रेस कॉंफ्रेंस कर संशोधन कानून देश को बांटने और अस्थिर करने वाला बताया। उन्होंने साझा बयान में कहा-यह देश के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। उन्होंने इसका विरोध किया और देश के राष्ट्रपति से अपील की कि वे इसपर अपनी सहमति न दें और पुनर्विचार के लिए इसे सदन में वापस भेजें। सोशलिस्ट युवजन सभा ने भी नागरिकता संसोधन विधेयक का विरोध किया। युवजन सभा की ओर से विशाल जोशी और प्रदीप साह ने कहा उनकी पार्टी इसपर सक्रिय आंदोलन करेगी। उन्होंने नागरिकों से सविधान्य अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने की अपील की।

12 पुलिसकर्मी घायल

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि हादसे में 12 पुलिसकर्मीयों और अधिकारियों को चोटें पहुंची हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। दोनों को पास अस्पताल के आइसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा भी जामिया पहुंचे। उन्होंने लाठीचार्ज और आंसू गैस की निंदा की और देषियों पर कार्रवाई की मांग की।

‘नब्बे फीसद महिलाओं को पसंद है आप’

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक सर्वेक्षण के आधार पर दावा किया कि दिल्ली की 90 फीसद महिलाएं आम आदमी पार्टी को पसंद करती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मदद नही बल्कि मौका चाहिए। उनको मौका मिलता है तो वे सीधे चौका लगाती हैं। वे नई दिल्ली में फिक्की महिला संघ के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को पंसद करने के लिए अलग- अलग तर्क दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में देश में महिला सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने खत हो सकता है तो महिलाओं को सुरक्षा भी दी जा सकती है, इसके लिए केवल व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की पुलिस बहुत अच्छी है। केवल व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है। एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मुप्त बस सफर 88 फीसद महिलाओं को पसंद आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधियों ने इसका खूब विरोध किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जितनी महिलाएं हैं, उसमें सिर्फ 11 फीसद महिलाएं बाहर काम करती हैं। मेट्रो में 33 फीसद ही महिलाएं और 67 फीसद पुरुष सफर करते हैं। डीटीसी में 30 फीसद महिलाएं व 70 फीसद पुरुष हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा, महिलाओं को आत्मविश्वास देने की जरूरत है। महिलाओं को भरोसा नहीं है कि पुलिस मदद देगी। उन्होंने कहा हमारे पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं अगर पुलिस को व्यवस्था को कहा जाए सुरक्षा दो, राजनीति नहीं चलेगी तो देगे। वह आत्मविश्वास लाना होगा। उन्होंने कहा कि जब स्कूल व अस्पताल ठीक हो सकते हैं तो पुलिस भी ठीक किया जा सकता है।

मेडिकल स्टोर में लगवाई दो साल की बच्ची को सुई, मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

जीटीबी एन्क्लेव थाना क्षेत्र में एक परिवार ने घर के पास के मेडिकल स्टोर में जाकर बिना डॉक्टर की सलाह के दो साल की बच्ची को दवा दी और इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिजनों का कहना है कि बच्ची को सर्दी-जुकाम हुआ था। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त अमित शर्मा का कहना है कि परिवार की शिकायत पर आरोपी स्टोर संचालक मनीष को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित परिवार जीटीबी एंक्लेव में रहता है। दो साल की बच्ची के पिता एक कारखाने में मजदूरी का

कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन से कहा : आपको बस कमरों का क्रमांक पता

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस बात पर हैरानी जताई कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को उन विद्यार्थियों के अकादमिक व्यौरों की कोई जानकारी नहीं है जिनके खिलाफ उसने अवमानना की याचिका दायर की है। विश्वविद्यालय का कहना है कि छात्रों ने प्रशासनिक ब्लॉक के 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन किया। न्यायमूर्ति एके

चावला ने विश्वविद्यालय से एक हलफनामा दायर करने को कहा है। इसमें उन छात्रों के पाठ्यक्रम, उनकी स्थिति और परिसर में उनके रहने की अवधि की जानकारी देने को कहा गया है जिनके खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई है। अदालत मामले पर सुनवाई अगले शुक्रवार को करेगी। अदालत ने कहा, ‘यह स्तब्धकारी है कि आप अवमानना का मामला दायर करते हैं लेकिन आपको विद्यार्थियों के बारे

झुग्गी वालों को मकान देगा डीडीए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

झुग्गी कॉलोनियों में रहने वालों को दिल्ली विकास प्राधिकरण 40 हजार मकान देगा। इसके लिए प्राधिकरण ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार को भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि ये मकान विभिन्न 32 कैम्प के निवासियों को मिलेंगे।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने 160 झुग्गी कैम्प को पक्का मकान बनाने के लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी प्रल्पूष कंठ, सह-प्रभारी नीलकांत बश्या समेत भाजपा ने अन्य नेता उपस्थित थे। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि

चेन्नई के शख्स ने मेट्रो के आगे जान दी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

जवाहर लाल नेहरू स्टैडियम मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर शुक्रवार को चेन्नई निवासी भगत से (33) ने मेट्रो ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम भगत को पास के राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह इन दिनों नोएडा स्थित एक निजी कंपनी में

डीडीए द्वारा धनराशि जमा कराने के बावजूद 10 माह तक पक्का मकान देने के लिए सर्वे को रोककर रखा था और इसकी जगह मुख्यमंत्री योजना के तहत सर्वे शुरू कर दिया था। इस बात को लेकर डीडीए ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर कहा कि सरकार नियमों नगरअंदाज कर सर्वे करा रही है। इसे तुरन्त रोका जाए। इसके उपरांत 20 अगस्त, 2019 को डीडीए ने स्वयं सर्वे शुरू कर दिया। 185 डिप्यूसिब कैंपों को डीडीए के सर्वे के अन्दर जोड़ने की मांग करते हुए कहा कि 5173 झुग्गीवासियों ने बैंक से लोन लेकर 68 हजार प्रति झुग्गी के हिसाब से दिल्ली सरकार को 39 करोड़ 40 लाख रुपए जमा करवाए, फिर भी दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें कोई भी पक्का मकान नहीं दिया।

खोज

काम कर रहे थे और नोएडा के सेक्टर-128 में ही किराए के मकान में रहते थे। पुलिस ने बताया कि उनके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस कारण आत्महत्या के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना की जानकारी परिवार को दे दी गई। उनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे पुलिस को सूचना मिली कि जवाहर लाल नेहरू स्टैडियम मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स ट्रेन के आगे कूद गया है।

पुआल से विकसित करेंगे बिजली बनाने की स्वदेशी तकनीक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

पुआल के बेहतर उपयोग व प्रदूषण का समाधान करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मद्रास ईंधन के रूप में धान के पुआल का उपयोग करके ताप विद्युत उत्पादन करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करेगा। आइआइटी का कहना है कि यह ‘स्टबल बर्निंग’ से निपटने के लिए अहम कदम होगा। पुआल खेतों में जलाने से मिट्टी क्षरण होता है। मिट्टी के फायदेमंद जीव नष्ट हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी हानिकारक गैसों व प्रदूषक कणों (पीएम) को उत्सर्जन होता है।

अकेले पंजाब और हरियाणा में हर साल 35 मिलियन टन धान की पैदावार होती है, जो मवेशियों के भोजन के लिए उपयुक्त नहीं है।

घर बैठे मिलेगा 30 और सरकारी सेवाओं का लाभ

में कुछ नहीं पता है। उनमें से एक पिछले साल अवमानना के मामले में दोषी पाया गया था।’ न्यायमूर्ति चावला ने कहा, ‘आपको बस (विद्यार्थियों के) कमरों का क्रमांक ही पता है।’ सुनवाई के दौरान मौजूद जेएनयू के रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी नौ विद्यार्थियों में उस गीता कुमारी का ब्योरा नहीं दे पाए जिसे विवि के अनुसार पिछले साल हाई कोर्ट ने प्रशासनिक प्रखंड के समीप प्रदर्शन करने को लेकर दोषी पाया था।

इन सेवाओं का अधिक उपयोग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

जनता को दिल्ली सरकार की 30 और नई सेवाएं अब घर बैठे उपलब्ध होंगी। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, प्रमाणपत्र, जांच समेत अन्य सरकारी दस्तावेज शामिल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार ने इन सेवाओं को डोर स्टेप डिजितीवरी सिस्टम के तहत जोड़ा है। नई सेवाओं के शामिल होने बाद घर बैठे मिलने वाली सेवाओं की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। अब जनता को विभिन्न 14 विभागों की सेवाएं इस व्यवस्था के तहत उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लगभग साल भर पहले दिल्ली सरकार ने एक खास प्रयोग कर इस व्यवस्था को शुरू किया था। इस सेवा के लिए दिल्ली सरकार ने एक कॉल सेंटर भी शुरू किया है। जिस पर जनता फोन करती है। इस व्यवस्था के जरिए किसी भी कागजात को बनवाने का तरीका अब जरूरी दस्तावेज फोन पर ही बना दिए जाते हैं।

इसके बाद कागजी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संबंधित व्यक्ति को घर बैठे ही प्रमाणपत्र उपलब्ध करा दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवहन, डीटीसी, श्रम, बाल कल्याण, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की सेवाओं को इस योजना से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि पिछले सवा

आइआइटी मद्रास कर रहा है इस परियोजना पर काम

हिंसक प्रतिशोध की गाथा



मर्दानी- 2

रेटिंग- ★★

निदेशक- गोपी पुत्रन

कलाकार- रानी मुखर्जी विशाल जेटवा, जित्तु सेनगुप्ता, दीपिका अमीन, श्रुति बापना

साल 2014 में रानी मुखर्जी की फिल्म आई थी मर्दानी। ‘मर्दानी-2’ उसी का सिक्वेल है। यह फिल्म महिलाओं के साथ हो रहे और बढ़ रहे बलात्कार की घटनाओं को लेकर बनाई गई है। राजस्थान के कोटा को केंद्र बनाकर कहानी गढ़ी गई है। यहीं पर पोस्टेड है पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी राॅय (रानी मुखर्जी)। और यहीं का है सनी (विशाल जेटवा) जो एक सीरियल रेपिस्ट है। सनी चालाक है, धूर्त है शातिर है और हृदयहीन है। उसे पकड़ना या कानून के फंदे में लाना आसान नहीं है। पर उसका सामना होता है एक ऐसी महिला पुलिस अधिकारी से जो न सिर्फ जांबाज है बल्कि महिलाओं के साथ होनेवाले किसी अत्याचार को मिटाने के लिए कटिबद्ध है। शिवानी सरेआम उन लोगों की धुलाई करती है जो महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यहार करते हैं। क्या शिवानी ऐसे चालाक अपराधी को कानूनी शिकंजे में ले पाएगी?

इसमे संदेह नहीं कि ‘मर्दानी-2’ उस समय आई है जब महिलाओं और लड़कियों के साथ यौन दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही हैं। पर यह उस समय भी आई है जो पुलिस कानून अपने हाथ में लेकर उन लोगों का काउंटर करते हुए उनकी हत्याएं भी कर रही है जिनपर बलात्कारी होने के आरोप



है। हैदराबाद एक हालिया उदाहरण है। यह फिल्म भी पुलिस के कानून में हाथ में लेने और अपराधियों को अपनी तरफ से दंड देने की वकालत करती भी दिखती है। ‘मर्दानी-2’ हिंसक प्रतिशोध की कहानी भी है। क्या ऐसे हिंसक प्रतिशोध का समर्थन किया जाना चाहिए। यह सवाल भी उठता है। हम एक न्यायप्रिय समाज बनाना चाहते हैं या प्रतिशोध से भरा समाज। हालांकि इस तरह के संदेश कई फिल्मों में आए हैं और आते रहे हैं। इसलिए मर्दानी-2 में जो दिखाया गया है उसमें नया कुछ नहीं है। यहां हिंसक यह कहा जा रहा है कि यह फिल्म यौन दुर्व्यवहार को जितनी संवेदनशील है उससे अधिक पुलिस द्वारा कानून को हाथ में लेने के समर्थन में खड़ी दिखती है।

रानी मुखर्जी पुलिस अधिकारी की भूमिका में जबर्दस्त रूप से दमदार हैं। कह सकते हैं कि ये फिल्म सिंधम जैसी फिल्मों की कड़ी में है जिसमें पुलिस अधिकारी को ईमानदार के साथ साथ अपराधियों की दुकाई करनेवाला दिखाया जाता रहा है। रानी अब अपने करिअर से उस दौर में जहां वह किसी रोमांटिक भूमिका के लिए नहीं रह गई है, इसलिए पुलिस अधिकारी की भूमिका में ही लीड रोल में आ रही है। अब भी वे अपने चेहरों पर जजबात दिखाने में सक्षम हैं। जहां तक फिल्म के खलनायक विशाल जेटवा का मसला है वे एक नई खोज की तरह हैं। हालांकि वे टेलीविजन के जौने माने कलाकार हैं पर अपने इस फिल्मी रूप में वे एक ऐसे शख्स के रूप में सामने आते हैं जो मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी क्रूर यानी साइको है। बिना किसी पश्चाताप के अपराध करनेवाला।

अगिनकांड में मारे गए मजदूरों के लिए धरना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति ने पिछले दिनों अनाज मंडी के अवैध कारखाने में आगजनी से मारे गए तीस मैथिल मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए धरना दिया। इसको अगुआई राजेंद्र शर्मा और संचालन शिशिर कुमार झा ने किया।

समिति के संयोजक अमरेंद्र झा और शिशिर कुमार झा ने दिल्ली, बिहार सरकार और उत्तरी दिल्ली नगर निगम से दस-दस लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। दोनों नेताओं ने पलायन के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार को नीतियों को दोषी ठहराया। उन्होंने पृथक मिथिला राज्य बनाकर मिथिला के सर्वांगीण विकास करवाने की अपील की। धरने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सांसद रामप्रीत मंडल, दिल्ली कांग्रेस के अभियान समिति के प्रमुख कीर्ति आजाद, गोपाल झा, विधायक संजीव झा आदि मौजूद थे।

आज के कार्यक्रम

रसा/संगोष्ठी

न्यू सोशलिस्ट इनेशिएटिव : हिंदी जगत और आधुनिकता विषय पर विचार गोष्ठी, गांधी शांति प्रतिष्ठान, दीन दयील उपाध्याय मार्ग, शनिवार शाम साढ़े पांच बजे।

के प्रबंध निदेशक जसवीर सिंह आवला ने कहा कि यह सहयोग पुआल जलाने की तकनीक को स्वदेशी बनाने और आयात से बचने के लिए किया गया है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत यह पहल की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में हर साल उपलब्ध पुआल से लगभग 4000 मेगावाट बिजली संभव है। इसे ग्रीनहाउस गैसों के बिना उत्पन्न किया जा सकता है इसके अलावा भूमि को जलने से बचाया जा सकता है। प्रौद्योगिकी विकास केंद्र बिजली संयंत्र के संचालन और रखरखाव के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम संचालित करके कौशल विकास केंद्र के रूप में भी काम करेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर वी राघवन ने कहा कि बॉयलरों के परिचालन मापदंडों में भारत के हिसाब से बदलाव किया जाएगा। इसे बॉयलरों के उत्सर्जन में कमी लाने और लंबे समय तक चलाने में सक्षम बनाना होगा।

सियासत की बीमारी संक्रामक हो गई है। दायरा सियासी दलों से बढ़कर साधु-संतों और खेल व खिलाड़ियों तक भी पहुंच चुका है। धर्म नगरी हरिद्वार में 2021 में आयोजित होने वाले कुंभ को लेकर भी संत अंधी से एक-दूसरे की टांग खींचने में जुट गए हैं। अखाड़ों की छावनीयों के लिए जमीन और खासी रकम की मांग कर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने अपना प्रभुत्व दिखाना चाहा है। सरकार को दबाव में लेने के मकसद से कुंभ के कामकाज की गति सुस्त होने का आरोप लगाया है। जबकि त्रिवेन्द्र सिंह रावत इस मामले में चुक करते नहीं दिख रहे। गिरि ठहरे मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के चहेते। संधी खेमे के साधु-संतों से पटती नहीं। तभी तो सूबे की भाजपा सरकार भी उन्हें ज्यादा भाव नहीं दे रही। वैरागी अखाड़े के महंत बाबा हट योगी उन पर खुलेआम शब्दबाण चला रहे हैं। उनकी अखाड़ा परिषद को ही फर्जी बता दिया। हट योगी तो सरकार से उलट मांग कर रहे हैं कि वह उन अखाड़ों को छावनी के लिए कतई जमीन न दे जिन्होंने अपनी छावनी में बहुमंजिला इमारतें बना रखी हैं। रही नरेंद्र गिरि की बात तो वे सरकार के शाइन बोर्ड बनाने के प्रस्ताव का भी विरोध कर रहे हैं। हट योगी इसके मुखर समर्थक बन कर उभरे हैं।

राजपाट

बढ़ती कलह

सत्ता की हनक अलग ही होती है। सत्ता से पार्टी कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होती है। नई सियासी रवायत तो यह भी कहती है कि मूल ध्येय सेवा नहीं सत्ता हथियाना होना चाहिए। नीति सिद्धांत बेमानी है। येन केन प्रकारेण या कहें कि साम-दाम-दंड-भेद कोई भी तरीका अपनाया जाए, बस सत्ता मिलनी चाहिए। गोवा और उत्तर-पूर्व के राज्य ही नहीं कर्नाटक की मिसाल पहले से थी। रात के अंधेरे में महाराष्ट्र में भी असफल कोशिश हुई थी। पर तीन दलों का मोर्चा भारी पड़ गया। बहरहाल सत्ता से दूरी होते ही महाराष्ट्र भाजपा में अंतरकलह सतह पर दिखने लगी है। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ पार्टी के पिछड़े और मराठा नेता लामबंद हो रहे हैं। एकनाथ खडसे और पंकजा मुंडे के सुर एकदम बागी हैं। सुगबुगाहट और भी कई स्तर पर जारी है। गुरुवार को बीड में पंकजा ने अपने दिवंगत पिता गोपीनाथ मुंडे की जयंती पर रेली कर खूब भड़ास निकाली। एकनाथ खडसे तो थे ही पार्टी के सूबेदार चंद्रकांत पाटिल की मौजूदगी हैरान करने वाली थी। पंकजा और खडसे ने फडणवीस का नाम लिए बिना खुद की उपेक्षा का ठीकरा उनके ऊपर फोड़ा। पंकजा ने फरमाया कि विधानसभा चुनाव के वक्त विनोद तावड़े और एकनाथ खडसे जैसे कद्दावर नेताओं के टिकट यह कह कर काट दिए गए कि आलाकमान ऐसा चाहता है। पर मेरी जानकारी है कि आलाकमान के बजाए सूबे के प्रभावशाली नेताओं ने यह खेल किया। संकेत फडणवीस की तरफ था। खडसे ने जहां पार्टी छोड़ने का संकेत दिया वहीं पंकजा ने ऐसा करने से इनकार किया। अलबत्ता चेतावनी के अंदाज में कहा कि वे साफगोई की राह नहीं छोड़ेंगी। खुद पार्टी छोड़ने का इरादा नहीं पर पार्टी उनके बारे में निर्णय को स्वतंत्र है। पंकजा ने कहा कि वे पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में नहीं गई थीं। पार्टी सीट पर अपनी हार के लिए भी उन्होंने फडणवीस को दोष दिया। साथ ही संकेत दिया कि वे अगले साल जनवरी में लोगों के बीच जाएंगी। रेली में खुद पंकजा ने लोगों से कहा कि वे चंद्रकांत पाटिल को हट न करें। खडसे ने फडणवीस पर हमला बोलते हुए यह भी कह दिया कि गोपीनाथ मुंडे की प्रतिमा देवेंद्र फडणवीस ने नहीं लगने दी। उन्होंने फडणवीस का नाम लिए बिना कहा कि वे पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ तो बोल ही सकते हैं जिन्होंने मीठी बातें करके अपनों की पीठ में ही छुरा भोंक दिया। मैंने न चोरी की और न भ्रष्टाचार। फिर मेरा टिकट क्यों काटा गया? खडसे ने अजित पवार से समर्थन लेने के लिए भी फडणवीस पर हमला बोला था। वे एनसीपी और शिवसेना नेताओं से भी मिल रहे हैं।

वक्त का फेर

टोटे में लड़ाई होती ही है, इस पुरानी कहावत को हम राजस्थान भाजपा में खरा साबित होते देख सकते हैं। साल भर पहले सूबे की सत्ता से बेदखल होते ही भाजपा में गुटबाजी सतह पर आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके विरोधियों के बीच ताकत दिखाने का खेल शुरू हो गया है। पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी थीं और फिर पद से हट गई थीं तो सूबे की सियासत से दूरी बना ली थी। वैसा ही इस बार भी दिख रहा है। चूंकि सत्ता में रहने का स्वभाव है सो विपक्ष की सियासत उन्हें रास आती भी नहीं। तभी तो भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ चाहे जो कार्यक्रम करे, वसुंधरा उससे दूर ही नजर आती हैं। पार्टी की बैठकों में शामिल होना भी वे अपनी तौहीन समझती हैं। ऊपर से आलाकमान ने उनके धुरविरोधी और आरएसएस के प्रति निष्ठावान सतीश पुनिया को पार्टी का सूबेदार बना कर वसुंधरा को और चिढ़ा दिया। सो, वे तो संगठन से दूर हैं ही, उनकी सरकार में सत्ता की मलाई खाने वाले दूसरे कई नेता भी संगठन के काम में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। सूबे में इन दिनों भाजपा में मंडल और जिला स्तर के संगठन चुनाव चल रहे हैं। पर वसुंधरा को कोई रुचि नहीं। निचले स्तर पर संगठन में अब संधी खेमे का दबदबा है। तो भी वसुंधरा खेमे के नेता दावा कर रहे हैं कि चार साल बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो वसुंधरा राजे की कद्र करनी ही होगी। यानी फिर चलेगी तो उन्हीं की। हालांकि, वसुंधरा खेमा भ्रम का शिकार लगता है। पार्टी की आबेहवा बदल चुकी है। आलाकमान अब वसुंधरा जैसे नेताओं से छुटकारा पाने की जुगत में है। तभी तो नया नेतृत्व उभारा जा रहा है। कोटा के ओम बिरला का लोकसभा अध्यक्ष बनना महज संयोग नहीं है। केंद्र में मंत्री भी नए हैं। वसुंधरा के बेटे को संसद में वरिष्ठता के बावजूद राज्यमंत्री तक का पद नहीं मिल पाया। नए सूबेदार सतीश पुनिया अपने पांव जमा रहे हैं। पिछले दिनों विदेश यात्रा से वापस आए तो जवपू में ऐसा भव्य स्वागत हुआ मानो वे पार्टी अध्यक्ष न होकर मुख्यमंत्री बनने वाले हों। नारे भी लगे कि मुख्यमंत्री कैसा हो, सतीश पुनिया जैसा हो। वसुंधरा खेमे को समझ क्यों नहीं आ रहा कि आलाकमान की सहमति के बिना इस तरह के नारे कौन लगा सकता है।

बम बम भाजपा

नागरिकता संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से तो पारित हो गया पर उत्तर-पूर्व के राज्यों में इसकी जैसी प्रतिक्रिया हुई है, वह भाजपा के लिए खतरों की घंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद भाजपा ने देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के सात राज्यों में अपना प्रभाव बेशक बढ़ाया। वहां अलगाववाद की सुलगीत आग भी काफी ठंडी पड़ गई थी। पर इस विधेयक के बाद तो हालत इस कदर बेकाबू हो गए कि कर्पूर्व भी लगाना पड़ा और सेना को भी बुलाना पड़ गया। पर ऐसा नहीं कह सकते कि भाजपा को इस प्रतिक्रिया का अंदाज न रहा हो। असम के मुख्यमंत्री ने तो पहले ही कह दिया था कि इस विधेयक का विरोध होगा। पर बड़े फायदे के लिए कुछ जोखिम लेना ही पड़ता है। उत्तर-पूर्व में जनजातियों के विरोध से जितना ज्यादा नुकसान होगा, उससे कहीं ज्यादा फायदा भाजपा को शेष भारत में मुसलमान विरोधी धुवीकरण बढ़ने से होने का अनुमान है। विपक्ष चौख कर कहता रहा कि मजहब के आधार पर भेदभाव की संविधान का अनुच्छेद 14 इजाजत नहीं देता। यह भी कि बहुमत के दम पर संविधान की मूल भावना के खिलाफ कोई कानून पारित नहीं किया जा सकता। पर तीन तलाक व धारा 370 के बाद नागरिकता कानून के एजेंडे को भाजपा ने लागू कर ही दिया। राममंदिर का सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी उसके मनमाफिक ही आया है। ऐसे में अगला कदम समान नागरिक संहिता का होना स्वाभाविक है। विपक्ष के पास अब कानूनी जंग के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है। पर रफाल व अयोध्या विवाद की अदालती जंग हार चुका विपक्ष इस मुद्दे पर भी अनुकूल अदालती फैसले की उम्मीद आत्मविश्वास के साथ तो नहीं कर सकता।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

विरोध कर रहे लोगों के साथ? आज के दौर में जब नागरिक स्मार्ट फोन के डाटा में तब्दील हो गए हैं और इतिहास वाट्सऐप के कारखाने से संपादित होकर अग्रेषित है तो गांधी के सरोकारों को कैसे समझाया जाएगा। बीसवीं सदी में विश्वविद्यालयों से निकले छात्र नेता जो इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ थे इक्कीसवीं सदी में वे सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों और शिक्षकों से बात करने को तैयार नहीं हैं। सत्ता के अहंकार और विखंडित विपक्ष में फंसी जनता पर बेबाक बोल।



मुकेश भारद्वाज

बोध और विरोध

मेरी हस्ती से हर शख्स बेजार क्यों है

हर हाथ में मेरे लिए तलवार क्यों है

मैं तो खुद ही तैयार हूँ महफिल से विदा होने को

फिर यह रोज-रोज की तकरार क्यों है।

यह सवाल जनता की तरफ से है जो जनतंत्र की बुनियादी शर्त है। पर संसद का सीधा प्रसारण बता रहा है कि जनता से लोकतंत्र के मंदिर (आधुनिक बोध के हिसाब से संसद के लिए मंदिर शब्द का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए) में कमजोरों के प्रति अहंकार की भाव-भंगिमा है, वह जरूर नया है। संसद में वित्त मंत्री का उच्चारण और भाव-भंगिमा उन लोगों पर लानत भेज रहा था जो लहसुन-प्याज खाते हैं। जैसे लहसुन-प्याज न खाने वाले कितनी उच्च कोटि के हो गए और खाने वाले एकदम अधम। वित्त मंत्री का अहंकार बताता है कि संसद में बैठे लोगों और जनता के बीच दूरी कितनी बढ़ गई है। कांग्रेस के 'संभ्रांत' नेता शशि थरुन ने जब हवाई जहाज की सामान्य श्रेणी को मवेशी वर्ग (कैल्ट क्लास) कहा था तो भी हंगामा मचा था। मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद जब बार-बार कपड़े बदलने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटील पर सवाल उठाया गया तो उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। अब तो दिखावे के नाम पर भी 'लोकतांत्रिक दिखावा' बंद कर दिया गया है।

मंदी का कारण यह नई पीढ़ी है जो गाड़ियां खरीदने के बजाए ओला और उबर से चलती है। सिनेमा हॉल में टिकट बिक रहे हैं, फिल्में सौ करोड़ का कारोबार कर रही हैं तो मंदी कहा है। अगर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी है तो फिर सड़कों पर इतना जाम क्यों लग रहा है। भारत में अभी तक ऐसा अध्ययन नहीं हुआ है जिससे पता चले कि प्रदूषण के कारण मौतें हो रही हैं। ऐसे बयान देते वक्त माननीय सांसदों को देह से जो अहंकार फूटता दिखाता है, उससे यही लगता है कि संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण नहीं होता तो कुछ भ्रम बचा रहता, नागरिकता के प्रमाणपत्र पर गर्व तो महसूस किया जा सकता था। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द राहत मिलेगी, यह विपक्ष की साजिश है, अंतरराष्ट्रीय कीमते बढ़ रही हैं जैसे दिलासा देनेवाली भाषा की भी अब जरूरत महसूस नहीं की जा रही। सारी पदेंदारी खत्म है। हमारा करने का मन है इसलिए ऐसा किया, हम यही करने के लिए आए हैं इसलिए ऐसा किया। रामराज्य में भी अपराध शून्य नहीं हो सकता। सरकार सभी को नौकरियों नहीं दे सकती है। लोग बच्चे पैदा कर सरकार के भरोसे छोड़ देते हैं। अगस्त में बच्चे मरते ही हैं जैसे चाक्य बोल कर नेता उसे संदर्भ सहित सही साबित करने में जुट जाते हैं और विपक्ष वैसी जिंदा कौम नहीं रह गई है कि पांच साल के पहले कुछ सोचे भी।

जनता तो अब स्मार्टफोन में तब्दील हो रही है, जहां नागरिकता बोध का कोई अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) ही नहीं। इतिहास किताबों से निकल



असम में विरोध प्रदर्शन करते लोग।



दिल्ली के शरणार्थी शिविर में जश्न मनाते लोग।

कर वाट्सऐप के कारखाने से संपादित होकर अग्रेषित है। सत्ता की क्रूरता मीम है और जनता की जंग चुटकुला। एक वर्ग को निःशुल्क शिक्षा के लिए हड़ताल करते जेएनयू के विद्यार्थी दुश्मन लगते हैं और वह अपने आयकर का हिसाब मांगने लगता है। वह अब किसी भी सरकार से सवाल नहीं करता। सत्ता के लिए इससे सुखद स्थिति क्या हो कि जनता ही जनता से लड़े और वहीं एक-दूसरे से जवाब मांगे।

उदारीकरण की अर्थव्यवस्था की नाकामी का कोई हल नहीं दिख रहा था तो दुनिया भर में इसका ठीकरा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही फोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता शब्दों को खारिज किया गया। आधार संख्या को बुनियादी जरूरतों के वास्ते अनिवार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान महाधिवक्ता दलील देते हैं कि नागरिकों के शरीर पर राज्य का अधिकार होता है। लोकतंत्र सत्ता के कर्तव्य और जनता के अधिकारों के लिए बनाया गया लेकिन अब इसे उलटा अर्थ दिया जा रहा है। अब सत्ता के पास अधिकार और अहंकार है और जनता के पास सिर्फ कर्तव्य।

सत्ता के अहंकार को दूर करने के लिए फिलहाल तो दूर-दूर भी विकल्प नहीं दिख रहा है। जोड़-तोड़ की बात छोड़ दें तो कर्नाटक के उपचुनाव में वे भी भाजपा सांसद चुन कर आ गए जो दलबदल कानून के तहत सदन से बेदखल थे। जद (सेकु) और कांग्रेस को नकारते हुए जनता ने फिर उन्हें सदन में पहुंचा दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वक्त जो राजनीतिक विश्लेषण हुए थे उपचुनावों के बाद वे सिर्फ बगलें ही झांक सकते हैं। जब राजनीतिक टिप्पणियों की उम्र इतनी छोटी हो जाए, सत्ता और जनता विपरीत व्यवहार करे तो फिलहाल थोड़ी देर रुक कर सोचने-समझने की कोशिश करनी चाहिए।

सत्ता और जनता दोनों संक्रमणकाल से गुजर रहे हैं। राममनोहर लोहिया की मशहूर उक्ति है कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवाज हो जाएगी। लेकिन अभी तो सड़क पर जनता है, पुलिस की पानी की बौछार और हिरासत में लेने का दौर है। सड़क

पर खड़ी इस जनता का संसद तक असर होगा? मौजूदा सरकार में जब वरिष्ठ मंत्रियों और सलाहकारों की सूची देखें तो इनमें से ज्यादातर चेहरों का करिश्मा आपातकाल के दौरान उभरा था। 1975 के विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र कांग्रेस के खिलाफ विकल्प बनकर संसद पहुंचे और वही लोग आज सड़क पर बैठे शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों को अलोकतांत्रिक बता रहे। सूनी सड़क से आवाज संसद की आशंका जताने वाले के कई शिष्य आज नागरिकता संशोधन बिल के पक्ष में खड़े हैं।

देश महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं जयंती मना चुका है और विभाजन के इतिहास के पन्ने अपनी-अपनी सुविधानुसार और अपने-अपने फुटनोट के साथ सामने लाए जा रहे हैं। विभाजन के इतिहास में दर्ज है महात्मा गांधी और नोआखली। गांधी नोआखली में अकेले घूम रहे थे क्योंकि एक बड़ी कौम को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था। आजादी के बाद से न जाने कितने नोआखली बने लेकिन वहां जनता की सुरक्षा के लिए अकेले घूमने वाले गांधी नहीं मिले। नोआखली की न जाने कितनी प्रतिकृति (क्लोन) तैयार हुई पर गांधी जो गए तो फिर किसी तरह नहीं बने। आज गांधी होते तो किधर जाते? नागरिकता बिल के विरोध में जल रहे असम की तरफ या दिल्ली में अभावों की गडरी के साथ मजदूर का टीला पर जश्न मनाते पाकिस्तान से आए उस हिंदू शरणार्थी की तरफ जिसने जन्म ली नवजात का नाम नागरिकता रखा है। देश कागज पर खींचा आसान नक्शा नहीं होता बल्कि मजदूर का टीला से लेकर असम तक की जटिलता होता है। इस जटिलता का हमारे देश में ही क्या पूरी दुनिया में गांधी के अलावा कोई हल नहीं है।

संसद, सड़क और जनता के रिश्ते में एक बार फिर से खारिज नागरिक ही है। बस इस नकारनाम पर दस्तखत करने वालों की कलम की स्याही बदल गई है। कागज और कलम के रिश्ते में स्याही का रंग आगे क्या रूप लेता है, उस पर आज इतनी जल्दी बोल कर कल खारिज होने का जोखिम कैसे लें।

इस विशेष पन्ने पर आपके डेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुकामिन् नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपको

पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं।

हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

नैतिकता की भी जरूरत

यौन हिंसा के मामले घर की चारदीवारी के अंदर भी होते हैं। लेकिन समाज में झूठी शान और बेइज्जती के डर से उन्हें घर की चारदीवारी के अंदर ही रफा-दफा कर दिया जाता है, जिससे अपराधियों के होसले बुलंद हो जाते हैं। देश में बलात्कार के बढ़ते अपराध बहुत बड़ी चिंता का विषय हैं। अगर इन पर नकेल कसने के लिए अभी गंभीरता नहीं दिखाई गई या फिर इसके लिए प्रयास सरकार और समाज ने मिलजुलकर नहीं किए तो आने वाला समय इससे भी विकट हो सकता है। सख्त कानून के साथ-साथ जब तक लोगों में नैतिकता की भावना का प्रचार-प्रसार नहीं होगा तब तक शायद ऐसी धिनीनी घटनाओं पर रोक लगना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अंत में यह भी कहना उचित होगा कि अगर बच्चों को बचपन से ही नैतिकता का सबक पढ़ाया जाए तो हमारे समाज में बढ़ रहे गलत कामों पर लगाम लग सकती है। आज के बच्चे कल के भविष्य होते हैं।

- राजेश कुमार चौहान।

हालात का पोस्टमार्टम

आर्थिक उदारीकरण के दौर में व्यस्ततम जीवन-शैली ने बच्चों के साथ हमारा संबंध सीमित कर दिया है। हम उन्हें परिपक्व सोच नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में भला महज कानून के सहारे अपराध पर नियंत्रण संभव नहीं। किस-किस को और कहा-कहां मारेंगे हम, जब समाज की मानसिकता ही हमारी

अपनी कमजोरी के कारण बीमार होते जा रही है? कानून जो भी बने, जितना भी सख्त बने जरूरत है इस बात की है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिलनी चाहिए तभी सुधार संभव है।

-डॉ. हर्षवर्द्धन, शिक्षाविद, लोहानीपुर-कदमकुआं, पटना।

भरोसा न टूटे

वहां एक लड़की नहीं इंसानियत जल रही थी। सड़क से सदन तक इस कदर भरोसे टूटते रहे तो एक दिन शब्दकोश से भरोसे और यकीन जैसे लपज ही गायब हो जाएंगे। एक बार रुक कर सोचें तो सही कि अदालतें न रही तो भरोसा किस चौखट खड़ा मिलेगा। वक्त रहते वो सारे जतन करने होंगे जिस से किसी का भरोसा न टूटे। वरना इस मुक्त की तबाही रोक पाना यकीन मुश्किल हो जाएगा।

-एमके मिश्रा, मां आनंदमयीनगर, रातू।

हल निकालना ही होगा

कमजोर पर मजबूत का वर्चस्व सदियों से चला आ रहा है। सामूहिक बलात्कार और बलात्कार के बाद लड़की को मार डालने की बढ़ती जा रही प्रवृत्ति खोफनाक है। समाज और शासन की सभी संस्थाओं को अपनी कमियां खोज इसका हल निकालना ही होगा।

-पारस एफ खेमसरा, 205 तिरुपति विहार, मध्य प्रदेश।

सही नेतृत्व की जरूरत

सबसे पहला कदम संसद को बढ़ाना होगा कि न्याय प्रक्रिया को मजबूत करने की ओर प्रयास किए जाएं। इसके बाद घर और समाज अपनी जिम्मेदारी निभाए कि बच्चे देश के जिम्मेदार नागरिक बनें। नागरिक बोध को बढ़ाकर ही हम हिंसक मानसिकता से पीछा छुड़ा सकते हैं।

- नितेश कुमार सिन्हा, मोतिहारी, बिहार।

घटना कानून का इकबाल

सवाल कानूनी नीति का नहीं बल्कि नीयत का है क्योंकि कोई भी खास घटना के विरुद्ध आयोजित कैंडल मार्च की लौ समय की रफ्तार और संवेदनाओं की शून्यता में 'हो हुआ सो हुआ' के समझौते का सारथी बन जाता है। उम्मीद के होसले समाधान की पटकथा लिख सकेगा तभी तो किसी ने कहा है, 'आसमानों से बरसता है ये अंधेरा कैसा, अपनी पलकों पे लिए जश्न-ए-चिरागों चलिए'।

-डॉक्टर अशोक कुमार, पटना।

भीड़ समाधान नहीं

'बलात्कारियों को भीड़ के हवाले कर देना चाहिए' ये बयान तो निश्चित रूप से पाषाणकालीन बर्बर युग की पुनरस्थापना करने का एक कुत्सित और घृणित कृत्य ही है।

-निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद।

संसद सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित

कई अहम विधेयक पारित, राज्यसभा के सत्र को ऐतिहासिक बताया नायडू ने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

संसद का 18 नवंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। इस दौरान लोकसभा एवं राज्यसभा, दोनों में कामकाज का फीसद सौ फीसद से अधिक रहा। सत्र के दौरान नागरिकता संशोधन विधेयक, एससी/एसटी आरक्षण को दस साल आगे बढ़ाने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक और ट्रांसजेंडर विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने अपने पारंपरिक भाषण में सत्र के दौरान हुए कामकाज पर संतोष जताते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर अपने पारंपरिक भाषण में कहा कि सभा की उत्पादकता 115

फीसद दर्ज की गई।

सत्र के दौरान नागरिकता (संशोधन) विधेयक तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण को दस साल बढ़ाने संबंधी संविधान (126वां) संशोधन विधेयकों पर सदन में लंबी चर्चा हुई तथा विपक्ष एवं सत्तापक्ष के लोगों ने खुल कर अपने विचार रखे। इस दौरान ई सिगरेट पर रोक लगाने संबंधी विधेयक, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र संबंधी विधेयक सहित विभिन्न विधेयकों को चर्चा कर पारित किया गया।

साथ ही उच्च सदन में लंबे अंतराल के बाद अनुदान की अनुपूरक मांगों को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाया गया। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान सदन की 20 बैठकें हुईं, जो 130 घंटे 45 मिनट चलीं। 2019-20 के लिए अनुदान की

अनुपूरक मांगों पर पांच घंटे और पांच मिनट चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान 18 सरकारी विधेयक पुनःस्थापित हुए और कुल मिला कर 14 विधेयक पारित हुए।

बिरला ने कहा कि 140 तारकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। औसतन प्रतिदिन लगभग 7.36 प्रश्नों के जवाब दिए गए। इसके अलावा प्रतिदिन 20.42 अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर दिए गए। प्रतिदिन औसतन 58.37 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन कुल 364 मामले उठाए गए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार सभा की उत्पादकता 115 फीसद दर्ज की गई। राज्यसभा में सत्र के दौरान 108 घंटे 33 मिनट तक निर्धारित कामकाज होना था। विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के चलते सदन के कामकाज में 11 घंटे 47 मिनट का नुकसान हुआ। किंतु सदस्यों ने 10 घंटे 52 मिनट अधिक काम कर सदन को उत्पादकता को 100 फीसद पर ला दिया।

सत्र के दौरान उच्च सदन में कुल 15 विधेयक पारित किए गए या विचार कर लौटाए गए। इनमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक शामिल है जो इस तरह के व्यक्तियों के हितों के लिए लाया गया अपनी तरह का पहला विधेयक है। सत्र के दौरान सदस्यों ने दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा शून्यकाल में एवं विशेष उल्लेख के जरिए लोकमहत्त्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। यह सत्र प्रश्नकाल के लिहाज से भी 1971 के बाद पिछले 49 सालों में सबसे बेहतरीन रहा। इस दौरान कुल 255 मौखिक सवालों में से 171 के जवाब दिए गए जो कुल सवालों का 67 फीसद है। इस प्रकार सत्र के दौरान प्रतिदिन 9.5 मौखिक सवालों के जवाब दिए गए। सभापति ने राज्यसभा के 250वें सत्र को ऐतिहासिक सत्र करार देते हुए कहा कि इसकी ‘गंभीरता एवं संक्षिप्तता’ महत्त्वपूर्ण रही।

जापानी प्रधानमंत्री का भारत दौरा रह

जापान सरकार ने नई दिल्ली को साफ बता दिया कि बड़े स्तर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर आबे के लिए गुवाहाटी आना संभव नहीं होगा। उन्होंने बताया कि बैठक अगले साल होने की संभावना है।

विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह आबे के दौरे की तारीखों की घोषणा की थी, लेकिन आयोगन स्थल का जिक्र नहीं किया था। हालांकि, शिखर सम्मेलन के लिए गुवाहाटी में जोर शोर से तैयारियों की जा रही थीं। जापान सरकार की एक टीम ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को गुवाहाटी का दौरा किया, जिसके बाद तोक्यो ने विदेश मंत्रालय को बताया कि मौजूदा परिस्थिति में आबे का दौरा नहीं हो सकता। जापानी अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। जापान ने उन अधिकारियों की रिपोर्ट की प्रतियां भारत के विदेश मंत्रालय को भी सौंपी हैं।

कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग पहुंची भाजपा की महिला सांसद

नई दिल्ली/इंदौर, 13 दिसंबर (भाषा)।

भाजपा ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से कहा कि झारखंड की चुनावी रैली में राहुल गांधी की ‘रेप इन इंडिया’ टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अगुवाई में भाजपा की महिला सांसदों ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ ‘कठोरतम संचय कार्रवाई’ की मांग की।

ईरानी ने कहा कि भाजपा की महिला सांसद इतनी नाराज हैं कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग से संपर्क किया। उन्होंने चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा, ‘हमने निर्वाचन आयोग से कहा कि यह पहली बार है जब किसी राजनीतिक नेता ने राजनीतिक मजाक के लिए बलात्कार का इस्तेमाल किया है। पूरा देश इस संवैधानिक संस्था (चुनाव आयोग) की ओर देख रहा है

तक महिलाओं की गरिमा को बरकरार रखा जा सके और जो नेता बलात्कार को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।’ ईरानी ने कहा कि उन्होंने यह निर्वाचन आयोग पर छोड़ा है कि गांधी को क्या सजा दी जाए।

उन्होंने पूछा कि किसने राहुल गांधी को अपनी राजनीतिक विचार देश की छवि को धूमिल करने का अधिकार दिया है? ईरानी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया कि वह कानूनी प्रक्रिया के अनुसार न्याय करेगा। इस बीच, इंदौर के एक स्थानीय भाजपा नेता ने मुकेश राजावत शुक्रवार को यहां जिला अदालत में राहुल के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत दर्ज कराई। राजावत के वकील अमित सिंह सिसोदिया ने बताया कि जिला अदालत के एक न्यायाधीश ने इस शिकायत को भीपाल की एक विशेष अदालत को भेज दिया जिसे सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

मतों की संख्या में विसंगतियों पर चुनाव आयोग को नोटिस

पेज 1 का बाकी
से लंबित मामले के साथ संलग्न करते हुए कहा कि इन पर फरवरी, 2020 में सुनवाई होगी। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) और कॉमन कॉज ने अपनी याचिका में निर्वाचन आयोग की भविष्य के सभी चुनावों में आंकड़ों की विसंगतियों की जांच के लिए पुष्टा प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। एडीआर ने अपने विशेषज्ञों की टीम के शोध आंकड़ों की हवाला देते हुए कहा है कि 2019 में संपन्न हुए चुनावों में विभिन्न सीटों पर मतदाताओं की संख्या और मत फीसद और गिनती किए गए मतों की संख्या के बारे में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों मे गंभीर

विसंगतियां हैं। याचिका में दावा किया गया है कि उनके शोध के दौरान अनेक विसंगतियों का पता चला। याचिका में कहा गया है कि ये विसंगतियां एक मत से लेकर 1,01,323 मतों की हैं। जो कुल मतों का 10.49 फीसद है। याचिका के अनुसार छह सीटों पर मतों की विसंगतियां चुनाव में जीत के अंतर से ज्यादा थीं। याचिका में किसी भी चुनाव के नतीजों की घोषणा से पहले आंकड़ों का सही तरीके से मिलान करने और इस साल के लोकसभा चुनावों के फार्म 17सी, 20, 21सी, 21डी और 21ई की सूचना के साथ ही सारे भावी चुनावों की ऐसी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

‘मजबूत मालदीव के लिए भारत प्रतिबद्ध’

पेज 1 का बाकी
के बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने पिछले एक वर्ष में भारत और मालदीव के बीच बेहतर संबंधों एवं द्विपक्षीय संबंधों के सकारात्मक परिणामों पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि छठवीं संयुक्त आयोग बैठक में दोनों देश अपने साझा लाभकारी सहयोग को और गहरा बनाने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और आगे के रास्ते का खालका तैयार करेंगे। मोदी ने कहा, ‘भारत शांतिपूर्ण, समृद्ध, लोकतांत्रिक, मजबूत मालदीव के निर्माण के लिए वहां की सरकार के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है।’ मालदीव के विदेश मंत्री शाहिद ने भारत- मालदीव संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी दृष्टि और मजबूत नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।

पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठिठुरन

पेज 1 का बाकी
के सभी पर्वतीय जिलों में जिला प्रशासन ने तीन दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। नैनीताल में शुक्रवार को इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। औली जोशीमठ, बद्रीनाथ केदारनाथ, गंगोत्री-यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब रानीखेत में जम कर बफ गिरी। पर्यटक नैनीताल, रानीखेत, कौसाना, मसुरी, जोशीमठ और औली बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वही उत्तराखंड में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई। तीन लोग घायल हो गए।

पहाड़ों में मौसम ने अचानक करवट बदली और उच्च हिमालय क्षेत्रों में बीती रात से ही बर्फबारी शुरू हो गई। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के चलते उत्तराखंड कड़ाके की

सदी की चपेट में है। उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री, गंगोत्री, हर्षिल, हरकिदून घाटी के दर्जनों गांवों में करीब 10 से 15 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है। यमुना घाटी में भी बर्फबारी लगातार जारी है। यमुना जी का मंदिर भी बर्फ की चपेट में आ गया है। नैनीताल में शीतकाल की पहली बर्फबारी देखने को मिली। देर रात बरसात होने के बाद तड़के सवेरे बर्फबारी हुई जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे। नैनीताल में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि के बाद गुरुवार को मौसम का पहली बर्फबारी देखने को मिली। नैनीताल का तापमान शून्य से नीचे चला गया है। बर्फबारी के चलते पर्यटकों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। यमुनोत्री राजमार्ग बंद पड़ा है। यमुनोत्री राजमार्ग राड़ी टॉप व गंगोत्री राजमार्ग चंपावत

की कई सड़कें बंद पड़ी हैं। कुमाऊं मंडल के पुलिस उपमहानिरीक्षक जगत राम जोशी का कहना है कि सभी जिलों में एसडीआरएफ और पुलिस की टीम को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी शनिवार तक बर्फबारी के आसार हैं। बर्फबारी से कहीं नुकसान हो रहा है तो वही दूसरी तरफ सेब और चावल की खेती करने वाले किसानों को फायदा हुआ है।

केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री, हेमकुंड नैनीताल, पिथौरागढ़, मुंसियारी, टिहरी, पौड़ी, औली जोशीमठ, चमोली समेत पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण तापमान शून्य से नीचे चला गया है। उत्तराखंड के चारों धर्मों को बर्फ की चादर ने ढक दिया है।

दोषी की याचिका के खिलाफ अदालत पहुंची निर्भया की मां

पेज 1 का बाकी
को उसी वक्त सुनी जाएगी जब दोषी की पुनर्विचार याचिका सुनवाई के लिए आएगी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल नौ जुलाई को इस मामले के तीन अन्य दोषियों 30 वर्षीय मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि वह निर्भया मामले के चारों दोषियों की फांसी की सजा पर अमल करने के लिए जरूरी करार जारी करने की मांग की याचिका पर 18 दिसंबर को सुनवाई करेगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने यह देखते हुए कि दोषियों में से एक की पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना है, इस मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को तय की।

जजों ने कहा- हम किसी तरह की हिंसा नहीं चाहते। हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। हम फैसला लेंगे। इसमें संदेह नहीं कि फैसला आपके पक्ष में है लेकिन यह भी सही है कि यह अंतिम नहीं है।

मांगने से इनकार

भटकाने का आरोप लगाया और दावा किया कि उन्नाव की घटनाओं पर महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कुंभकरण की नींद में थीं और निर्भया कोष की विफलता पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। पार्टी प्रवक्ता सुभिता देव ने कहा, ‘मैं ये जरूर कहूँगी कि अगर हम रैली में किसान की बात कर सकते हैं, युवाओं की बेरोजगारी की बात कर सकते हैं तो महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार के ऊपर रैली में बोलने पर कोई रोक क्यों है?’ इससे पूर्व स्मृति ईरानी ने संसद भवन पत्रिस में कहा, ‘ उन्होंने (राहुल ने) महिलाओं के बलात्कार और उनकी पीड़ा को राजनीति के लिये इस्तेमाल किया।’

असम व पूर्वोत्तर की आग पहुंची बंगाल

पेज 1 का बाकी
कुछ इलाकों में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। असम के विभिन्न इलाकों में सेना की 26 टुकड़ियां तैनात कर गई हैं। नागरिकता कानून को लेकर चल रहे हंगामे की वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार और सोमवार को पूर्वोत्तर के दो राज्यों- मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का अपना दौरा रद्द कर दिया है। असम और मेघालय में इंटरनेट और ट्रेन सेवाएं टप हैं। इस बीच, प्रदर्शन और हिंसा की शुक्रवार को पश्चिम बंगाल तक पहुंच गईं। प्रदर्शनकारियों ने मुर्शिदाबाद में एक रेलवे स्टेशन फूंक दिया। राजधानी कोलकाता से सटे हावड़ा के उलूबेंडिया में छह घंटे से ज्यादा समय तक राष्ट्रीय राजमार्ग छह जाम कर दिया गया। फ्रंस ने अपने नागरिकों के लिए परामर्श जारी कर उन्हें असम और त्रिपुरा

सबरीमला पर किसी नए आदेश से इनकार

पेज 1 का बाकी
की रोक नहीं है लेकिन यह भी सही है कि यह अभी अंतिम नहीं है। पीठ ने कहा कि सात सदस्यीय पीठ को सौंप गए मुद्दों पर फैसला आने के बाद जल्द से जल्द पिछले साल सितंबर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसने कहा कि वह वृहद पीठ का निर्णय आने तक इस मामले में कोई आदेश नहीं देगा और यदि मंदिर में पूजा के लिए महिलाओं का सहर्ष स्वागत किया जाता है तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी।

एक याची के वकील ने जब जोर देकर कहा कि पिछले साल के निर्णय पर अदालत ने

पिछले दो दिनों से राजधानी गुवाहाटी में कर्फ्यू के बीच संवेदनशील इलाकों में स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए सेना के जवान भी तैनात हैं। इंटरनेट सेवाएं लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को भी बाधित रही हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार और सोमवार को पूर्वोत्तर के दो राज्यों मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का अपना दौरा रद्द कर दिया है। शाह का यह दौरा ऐसे समय रद्द किया गया है जब मेघालय और असम में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री को मेघालय की राजधानी शिलांग के निकट स्थित पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी के पासिंग आउट परेड में रविवार को शामिल होना था।

राज्यों को इनकार का हक नहीं : केंद्र

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकारों को नागरिकता कानून, 2019 को लागू करने से इनकार करने का अधिकार नहीं है। यह कानून संविधान की सातवीं अनुसूची की केंद्रीय सूची के तहत बनाया गया है।

गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘राज्यों को ऐसे किसी भी केंद्रीय कानून को लागू करने से इनकार करने का अधिकार नहीं है जो संघ सूची में है।’

राहुल के बयान पर लोकसभा में हंगामा, माफी मांगने की मांग

पेज 1 का बाकी
पर अध्यक्ष ने सत्र के बारे में अपना बयान देकर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। सिंह ने कहा, ‘देश एक निर्यातक देश के रूप में खड़ा हो जाए इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम पर बल दिया है। ‘मेक इन इंडिया’ के साथ जिस तरह की तुकबंदी सदन के वरिष्ठ सदस्य राहुल गांधी द्वारा की गई है, उससे पूरा देश आहत हुआ है। उनकी सदन ही नहीं बल्कि पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।’ इस दौरान सदन में

राहुल गांधी मौजूद थे। सदन में नारेबाजी के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दोपहर 12:15 बजे के तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन प्रश्नकाल आरंभ होने के साथ ही भाजपा की कई महिला सदस्य अपने स्थान पर खड़ी हो गईं और राहुल गांधी से माफी की मांग करने लगीं। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने संसद पर 2001 में आज के दिन हुए आतंकी हमले की घटना का जिक्र किया और सदन ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी।

खबर कोना



भारत-वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबले से पहले शुक्रवार को चेन्नई में प्रैक्टिस के दौरान भारतीय खिलाड़ी केदार जाधव।

आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी की दौड़ में

मेलबर्न, 13 दिसंबर (एफपी)।

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने महिला फुटबल विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी का दावा पेश किया है। फीफा इस विश्व कप में टीमों की संख्या 22 से बढ़ाकर 24 करने की सोच रहा है। अधिकारियों ने कहा कि दो देशों के मेजबान होने से अतिरिक्त मैचों के आयोजन में मदद मिलेगी। फीफा के अनुसार अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, जापान, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका भी मेजबानी की दौड़ में हैं। मेजबानी पर फैसला मई में लिए जाने की संभावना है।

अंडर-17 महिला फुटबल : स्वीडन से 0-3 से हारी भारतीय टीम

मुंबई, 13 दिसंबर (भाषा)।

भारत की अंडर-17 महिला टीम ने तीन देशों के फुटबल टूर्नामेंट में अपने अभियान की निराशाजनक शुरुआत की और उसे शुक्रवार को यहां अपने पहले मैच में ही स्वीडन से 0-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। स्वीडन की टीम ने भारतीयों की कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। उसकी तरफ से माल्टिडा विनबर्ग (चौथे मिनट), इडा वीनडेनबर्ग (25वें मिनट) और मोनिका जुसु बाह (90+1 मिनट) ने गोल किए। स्वीडन को चौथे मिनट में ही पेनल्टी किक मिली जिसे विनबर्ग ने गोल में बदला। स्ट्राइकर बाह को पेनल्टी बाक्स में गिराए जाने के कारण स्वीडन को यह पेनल्टी मिली थी।

पीसीबी का अशरफ, शिनवारी को एनओसी देने से इनकार

कराची, 13 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हरफनमौला फहीम अशरफ और तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी को आस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेलने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' देने से इनकार कर दिया। अशरफ और शिनवारी ने हाल ही में बीबीएल के साथ करार किया था। अशरफ ने मई के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है। उनके साथ मेलबर्न रेनेगेड्स ने करार किया था जबकि शिनवारी को इसी टीम ने पहले पांच मैचों के लिए अनुबंधित किया है। पीसीबी के एक सूत्र ने कहा कि अशरफ को घरेलू क्रिकेट पर फोकस करने के लिए कहा गया है जबकि शिनवारी को श्रीलंका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के लिए राष्ट्रीय टीम में चुना गया है।

आइपीएल नीलामी का हिस्सा बनेंगे 332 खिलाड़ी

दो करोड़ की सूची में कोई भारतीय नहीं

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 13 दिसंबर।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र के लिए होने वाली नीलामी के लिए 332 खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। 19 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली यह नीलामी की प्रक्रिया पहली बार सुबह की जगह दोपहर (3:30) में शुरू होगी। नीलामी में भाग लेने के लिए 997 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था। इसमें आस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन ने खुद को सबसे ज्यादा दो करोड़ रुपए वर्ग में रखा है।

दो करोड़ की सूची में पांच आस्ट्रेलियाई दो करोड़ रुपए के बेस प्राइस की सूची में सात खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। इसमें से पांच आस्ट्रेलियाई हैं। दिलचस्प यह है कि टी-20 विश्व कप की तैयारी में जुटी टीम इंडिया के किसी भी खिलाड़ी का नाम इस सूची में नहीं है। सभी खिलाड़ी विदेशी हैं। आस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस लिन, पैट कर्मिस, जोश हेजलवुड और मिशेल मार्श शामिल हैं। वहीं श्रीलंका के हरफनमौला एंजेलो मैथ्यूज और दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन ने भी खुद को इस सूची में रका है।

उथप्पा पर होगी सभी की निगाहें

इस बोली में सिर्फ 73 खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी टीमों के साथ जोड़ सकते हैं जिसमें केवल 29 विदेशी शामिल होंगे। फिच एक करोड़ रुपए के खिलाड़ियों की सूची में हैं। केकेआर से रितीज किए गए आस्ट्रेलिया के क्रिस लिन को इस बोली में अच्छी कीमत

1.5 करोड़ की सूची में अकेले भारतीय उथप्पा

डेढ़ करोड़ की बेस प्राइस में कुल दस खिलाड़ियों को जगह दी गई है। इसमें एकमात्र भारतीय रॉबिन उथप्पा हैं। बाकी नौ खिलाड़ी विदेशी हैं। इंग्लैंड के चार खिलाड़ियों ने इस सूची में जगह बनाई है। इसमें ईयान मॉर्गन, जैसन रॉय, क्रिस वोक्स और डेविड विली शामिल हैं। आस्ट्रेलिया के एडम जंपा, शॉन मार्श और केन रिचर्डसन नीलामी में भाग ले रहे हैं। दक्षिण अफ्रीकी टीम से काइली एबॉट और क्रिस मारिस इस बेस प्राइस सूची का हिस्सा हैं।

आइपीएल की आगामी सत्र के लिए शुरुआत में 997 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था। आठ फ्रेंचाइजियों से मिले चयनित खिलाड़ियों की सूची के बाद इसे छोटा कर दिया गया।

मिलने की उम्मीद होगी। उथप्पा के आलवा जिन भारतीय खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजियों की नजर होगी उसमें पीयूष चावला (केकेआर),



युसूफ पटान (सनराइजर्स हैदराबाद) और जयदेव उनादकट (राजस्थान रॉयल्स) शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी एक करोड़ रुपए की सूची

दो करोड़ की सूची में शामिल खिलाड़ी

दो करोड़ की सूची में सात खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें सभी सात खिलाड़ी विदेशी हैं। इन खिलाड़ियों में ग्लेन मैक्सवेल, पैट कर्मिस, जोश हेजलवुड, मिशेल मार्श, डेल स्टेन और एंजेलो मैथ्यूज।

भारतीय खिलाड़ियों की कीमत

1.5 करोड़ : रॉबिन उथप्पा
1 करोड़ : पीयूष चावला, युसूफ पटान, जयदेव उनादकट
50 लाख : चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, स्टुअर्ट बिन्नी, मोहित शर्मा
20 लाख : पवन देशपांडे, यशस्वी जायसवाल

में हैं। नीलामी में 186 भारतीय खिलाड़ी जबकि 143 विदेशी और एसोसिएट देशों के तीन खिलाड़ी शामिल हैं।

मानसिक रूप से थक चुका था : मैक्सवेल

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

आस्ट्रेलियाई हरफनमौला ग्लेन मैक्सवेल ने कहा कि पिछले चार या पांच साल से लगातार खेलते रहने के कारण वह मानसिक और शारीरिक तौर पर काफी थक चुके थे। इसी कारण उन्हें अक्टूबर में मानसिक स्वास्थ्य की वजह से आराम लेने को मजबूर होना पड़ा। मैक्सवेल श्रीलंका के खिलाफ पहले दो मैच खेलने के बाद अपने मानसिक स्वास्थ्य के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से हट गए थे।

उन्होंने कहा कि जब मैंने हटने का फैसला किया तो मैं काफी थका हुआ था। मैंने आराम लेने का फैसला क्यों किया इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि मैं मानसिक और शारीरिक तौर पर बुरी तरह थक चुका था। मैं लगातार आठ महीने से व्यस्त था और पिछले चार पांच वर्षों से ऐसा हो रहा था। मैं लगातार खेल रहा था और उस समय यह थकान मुझ पर हावी हो गई थी।

उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में क्रिकेट आस्ट्रेलिया, क्रिकेट विक्टोरिया और स्टार्स का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे खेल से बाहर रहने की अनुमति दी। मुझे सही स्थिति में लौटने के लिए समय दिया। मैक्सवेल ने कहा कि वह उनकी महिला मित्र थी जिसने सबसे पहले उनमें बदलाव महसूस किया। उन्होंने कहा कि असल में वह मेरी महिला मित्र थी जिसने मुझे किसी से सलाह लेने के लिए कहा। सबसे पहले उन्हें मेरे अंदर बदलाव का अहसास हुआ और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। शुरुआती बातचीत के बाद ही मुझे लगा कि जैसे मेरे कंधों से भारी बोझ उतर गया।



जापान के नगानो में स्पीड स्केटिंग विश्व कप में महिला स्प्रिट रेस के दौरान मुकाबला करती खिलाड़ी।

कपूर सात अंडर के शानदार कार्ड से संयुक्त पांचवें स्थान पर

जकार्ता, 13 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय गोल्फर शिव कपूर इंडोनेशिया मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट के दूसरे दिन शुक्रवार को सात अंडर 65 का शानदार कार्ड खेलकर संयुक्त पांचवें स्थान पर पहुंच गए। कपूर दूसरे दिन उन पांच गोल्फरों में शामिल रहे जिन्होंने दिन का सर्वश्रेष्ठ सात अंडर का कार्ड खेला। उन्होंने गुरुवार को पहले दौर में दो अंडर 70 का कार्ड खेला था जिससे उनका कुल स्कोर नौ अंडर का है।

शोष दस में एक अन्य भारतीय खिलाड़ी अजितेश

संधू भी है। पांच अंडर 67 का कार्ड खेलने वाला यह गोल्फर कुल आठ अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से आठवें पायदान पर है। राशिद खान ने भी दूसरे दौर में सात अंडर का शानदार कार्ड खेला। वह छह अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 14वें स्थान पर है। विराज मदप्पा (तीन अंडर 69) भी इसी पायदान पर है। कट हासिल करने वाले अन्य भारतीयों में ज्योति रंधावा (तीन अंडर 69) संयुक्त 30वें, एसएसपी चौरसिया (तीन अंडर 69) संयुक्त 39वें, अमन राज (एक ओवर 73) संयुक्त 50वें और अर्जुन अटवाल (एक अंडर 71) संयुक्त 60वें स्थान पर है।

तनसीम क्वार्टर फाइनल में, वरुण एशियाई जूनियर चैंपियनशिप से बाहर

सुराबाया (इंडोनेशिया), 13 दिसंबर (भाषा)।

भारत की तनसीम मीर ने एशिया बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप में शुक्रवार को लड़कियों के अंडर-15 वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया लेकिन वरुण कपूर लड़कों के अंडर-17 वर्ग से बाहर हो गए। गुजरात की तनसीम ने मलेशिया की वेन सी चान को केवल 20 मिनट में 21-6, 21-16 से हराया। उनका अगला मुकाबला जापान की माया तागुची से होगा।

लड़कों के अंडर-17 एकल में महाराष्ट्र के वरुण कपूर को इंडोनेशिया के रायनाल्डी ओक्टाविनो रिज्की से 19-21, 21-23 से हार का

सामना करना पड़ा। असम के तन्मय बिकास बरुआ ने हालांकि अंडर-15 डेनमार्क के फारेल सतरिया परदाना को 24-22, 21-15 से पराजित किया।

बरुआ ने लक्ष्य शर्मा के साथ अंडर-15 युगल में थाईलैंड के तनाकोर्न मीचा और टाइनुकुन तियाचान को 21-18, 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। लोकेश रेड्डी और अंकित मंडल की जोड़ी भी अंतिम आठ में पहुंच गई है। लड़कियों के युगल में आंद्रिया सराह कुरियन और पवित्रा नवीन की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा लेकिन

अंडर-17 वर्ग में जनानी अनंतकुमार और तान्या हेमंत की जोड़ी आगे बढ़ने में सफल रही।

मैच के आधार पर तय होगी रैंकिंग

लुसाने, 13 दिसंबर (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने शुक्रवार को 2020 के लिए नई विश्व रैंकिंग प्रणाली का अनावरण किया। इसमें रैंकिंग का निर्धारण टूर्नामेंट के आधार पर नहीं बल्कि मैच के आधार पर होगा। नई व्यवस्था अगले साल एक जनवरी से लागू होगी। एफआइएच ने कहा कि बारह महीने के गहन शोध, विश्लेषण और परीक्षण के बाद यह व्यवस्था शुरू की जा रही है।

2003 से जारी एफआइएच विश्व रैंकिंग प्रणाली मूल रूप से टूर्नामेंटों में टीमों को पूल में बांटने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत टीमों को साल में दो या तीन बार रैंकिंग अंक बनाने का मौका मिलता था। इससे निचली रैंकिंग वाली टीमों के पास कम मौके रह जाते थे और उनकी क्षमता का सही आकलन नहीं हो पाता था एफआइएच ने एक बयान में कहा कि करीब 60 फीसद अंतरराष्ट्रीय मैचों में कोई रैंकिंग अंक नहीं होते और यही देखकर हमें बदलाव करना पड़ा। नई प्रणाली के तहत एफआइएच से मान्यता प्राप्त हर मैच के लिए टीमों को रैंकिंग अंक मिलेंगे।

बिग बाउट मुक्केबाजी लीग में बंगलुरु ने पैथर्स को हराया

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

बंगलुरु ब्रॉलर्स ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग (आइबीएल) में चढ़ा उलटफेर करते हुए पंजाब पैथर्स को 4-3 से हराया। अनामिका (51 किग्रा) और कप्तान सिमरनजीत (60 किग्रा) ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर बंगलुरु को अच्छी शुरुआत दी। इनके अलावा दिनेश डागर ने चार मैचों में आज अपना पहला मैच जीता जबकि पवन

सिंधू ने बिंगजियाओ को हरा अभियान का अंत किया

ग्वांगजू, 13 दिसंबर (भाषा)।

खिताब की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी भारतीय बैडमिंटन स्टार पी वी सिंधू ने गुप ए के अपने तीसरे और अंतिम मैच में चीन की ही बिंगजियाओ पर सांत्वना जीत दर्ज करके वर्ष के आखिरी टूर्नामेंट

कुमार ने भी चार मैचों में पहली जीत दर्ज की।

अभी तक अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर 12 अंक जुटा चुकी पैथर्स ने इस मैच में चार मुक्केबाजों को लीग में पदापण का मौका दिया। टीम ने कप्तान एमसी मैरी काम, उज्बेकिस्तान के अब्दुलमलिक खालाकोव, मनोज कुमार को आराम दिया। इस हार से पैथर्स अंकतालिका में दूसरे स्थान पर आ गई है। पैथर्स के चार मैचों से 15 अंक हो गए हैं वह गुजरात जाएं ट्रेस से पीछे हैं जिसके चार मैचों में 17 अंक हैं।

बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल में अपने अभियान का सकारात्मक अंत किया। पिछले साल की चैंपियन सिंधू अपने पहले दोनों मैच गंवाने के कारण खिताब की दौड़ से पहले ही बाहर हो गई थी। बिंगजियाओ के खिलाफ भी पहले गेम में वह 9-18 से पीछे चल रही थी लेकिन इसके बाद उन्होंने वापसी की।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे से पहले

नेट पर गेंदबाजी करेंगे जसप्रीत बुमराह

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

कमर की चोट के बाद रिहैबिलिटेशन में जुटे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले नेट पर भारतीय टीम के साथ अभ्यास करेंगे। बुमराह स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला की शुरुआत से टीम से बाहर हैं। वह हालांकि अब ठीक होने की राह पर हैं। टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि अगले साल न्यूजीलैंड दौरे से पहले वह फिट हो जाएंगे।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा वनडे 18 दिसंबर को खेला जाएगा। बीसीसीआइ के एक सूत्र ने बताया कि बुमराह भारतीय टीम के साथ अभ्यास करेंगे। अब यह परंपरा बन गई है। टीम प्रबंधन ने भुवनेश्वर कुमार की फिटनेस भी इंदौर में बांग्लादेश के खिलाफ टैस्ट से पहले परखी थी हालांकि वह टीम का हिस्सा नहीं थे। इसी तरह बुमराह की फिटनेस को आजमाया जाएगा। सूत्र ने कहा कि अब यही परंपरा बन गई है कि जब कोई खिलाड़ी फिट होता नजर आता है तो टीम प्रबंधन, फिजियो और ट्रेनर नेट अभ्यास में उसे परखते हैं। बुमराह और हादिक पंड्या आइपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं और मुंबई के बीकेसी मैदान पर उनका रिहैबिलिटेशन चल रहा है। ऐसी भी संभावना है कि बुमराह को भारत 'ए' टीम के साथ न्यूजीलैंड भेजा जाए ताकि उन्हें अभ्यास मिल सके।

कुंबले बोले, अय्यर को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा)।

भारत के पूर्व कप्तान और महान स्पिनर अनिल कुंबले का मानना है कि श्रेयस अय्यर को वेस्ट इंडीज के खिलाफ आगामी वनडे श्रृंखला में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करना चाहिए। उनका मानना है कि भारतीय गेंदबाजों के लिए यह श्रृंखला चुनौतीपूर्ण होगी। कुंबले ने कहा कि भारतीय गेंदबाजों को वेस्ट इंडीज के मजबूत विकेट भी बल्लेबाजी के अनुकूल है तो बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ

प्रदर्शन करना होगा।

उन्होंने कहा कि विश्वर के नहीं होने से केएल राहुल को पारी के आगाज का मौका मिला है। श्रेयस अय्यर काफी परिपक्व बल्लेबाज हैं। मैं चाहूंगा कि वह चौथे नंबर पर उतरें। दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मैच चेन्नई में खेला जाएगा। कुंबले ने स्टार स्पॉटर्स से कहा कि वेस्ट इंडीज के सामने गेंदबाजी चुनौतीपूर्ण होगी। उनके पास दमदार हिटर्स हैं। गेंदबाजों को वेस्ट इंडीज के मजबूत विकेट भी बल्लेबाजी के अनुकूल है तो बल्लेबाजी क्रम को उम्दा प्रदर्शन करना होगा।



चोटिल भुवनेश्वर श्रृंखला से बाहर

चेन्नई, 13 दिसंबर (भाषा)।

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार चोटिल होने के कारण वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मुंबई के तेज गेंदबाज शारदुल ठाकुर को टीम में जगह मिल सकती है। भुवनेश्वर बुधवार को समाप्त हुई टी20

अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के दौरान चोटिल हो गए थे।

बीसीसीआइ के अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया, 'भुवनेश्वर श्रृंखला से बाहर हो गए हैं और शारदुल टीम में उनकी जगह लेंगे।' शारदुल बांग्लादेश के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला की टीम में थे और गुरुवार तक उन्होंने बड़ौदा के खिलाफ रणजी मैच में मुंबई का प्रतिनिधित्व किया था।